



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 18 सितम्बर, 2008 / 27 भाद्रपद, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

वहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

तारीख: 17 सितम्बर, 2008

संख्या: विद्युत.-छ-(5)-9/2007.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि कि नेशनल हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत एक केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः फाटी मन्थासी व दुसाहड़ कोठी वनोगी, उप तहसील सैज, जिला कुल्लू, हि०प्र० में पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण-III (सैज वाई पास रोड़ आर०डी० 2495 मी० से 3028 मी०) हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव: एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए यह घोषणा की जाती है कि उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, पार्वती जल विद्युत परियोजना, लारजी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को एतद्वारा भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्याधिक आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, पार्वती जल विद्युत परियोजना, लारजी, जिला कुल्लू, हि0प्र0 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-(1) के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, पार्वती जल विद्युत परियोजना, लारजी, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	उप तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकबा (बीघों में)
कुल्लू	सैज	फाटी मन्यासी कोठी वनोगी	1868/22/2/1	1-03-08
			1869/22/1/1	1-01-12
कुल कित्ता -2			कुल रकबा-2-05-00 बीघा	

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव।

कार्मिक विभाग

सचिवालय प्रशासन सेवाएँ

अधिसूचना

शिमला-2, 1 फरवरी, 2008

संख्या: कार्मिक (सचि0 प्रशा0-1)ए(3)-1/85-1.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या. कार्मिक (सचि0 प्रशा0-1) (ए-3) 3/83 तारीख 30-05-97 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) माली वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियमों में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन), माली वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपाबन्ध-अ का.**—हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएँ) माली वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम 1997 के उपाबन्ध 'अ' में :—

(क) स्तम्भ संख्या 6 में, आए अंकों और शब्दों में "18 से 38 वर्ष" के स्थान पर "18 से 45 वर्ष" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के विधामान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता”

(ग) स्तम्भ 10 के सामने विद्यमान उपाबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः—

“शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर”

(घ) स्तम्भ संख्या 14 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः—

“किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य हैं”
और

(ङ) विद्यमान स्तम्भ संख्या 15 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

15—क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सचिवालय में माली को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) अभ्यर्थियों को, दो अग्रिणी समाचार पत्रों में रिक्त पदों का विज्ञापन देकर चयनित किया जाएगा।

(ग) चयन भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार का चयनित संविदा पर नियुक्ति माली को किसी भी दशा में सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेसन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा पर नियुक्त माली को 3930/— रूपए की समेकित संविदात्मक रकम (अर्थात् वेतनमान का प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 100/—रूपए की रकम वार्षिक वृद्धि अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—सरकार द्वारा समय-समय पर यथा जारी स्थाई आदेशों के अनुसार।

(IV) चयन प्रक्रिया.—(क) सचिवालय प्रशासन विभाग, रिक्तियों को भरने के लिए पूर्ण औचित्य सहित ठीक अग्रिम में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(ख) विभाग रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पदों के ब्योरे दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताओं और इन नियमों में यथा विहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्ति/भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) चयन के लिए समिति.—सक्षम प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा गठित।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—“ख” के अनुसार सरकार के साथ हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा पर नियुक्त माली को 3930/— रूपए की नियत संविदात्मक रकम (अर्थात् वेतनमान का प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त

व्यक्ति, क्रमवर्ती द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 100/-रुपये (वेतनमान के वार्षिक वृद्धि के बराबर) की दर से वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा। उपरोक्त समेकित रकम के सिवाए और कोई अन्य सहब प्रसुविधाएं जैसे कोई उच्चतर ग्रेड इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतयः अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदात्मक नियुक्त, पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितिकरण को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेंगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और उसके पश्चात् व्यपगता हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को केवल प्रसूति अवकाश सम्बन्धित छुट्टी नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। ऐसे व्यपगमनों में कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवस्था प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर से जैसे प्रतिस्थानी नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ती और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए हकदार होगा।

(झ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार.—इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में माली के रूप में नियमितिकरण/स्थाई आमेसन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव।

**माली और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य..... (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के माध्यम से
संविदा की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप**

यह करार श्री/श्रीमति..... पुत्र/पुत्री श्री.....
..... निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य..... (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के माध्यम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) आज तारीख..... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने माली के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार माली के रूप में से प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात् दिन को स्वयंसेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 3930/- रुपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
5. संविदा पर नियुक्त माली एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त माली को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (सम्पन्न) हो जाएगा। संविदात्मक माली कर्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा/होगी।
7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण, किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।
8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी आरम्भिक वेतनमान के नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का वेतनमान के न्यूनतम पर हकदार होगा/होगी।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में सर्व प्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

 (नाम व पूरा पता)

2.....

 (नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

 (नाम व पूरा पता)

2.....

 (नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

[Authoritative English text of this Department Notification No. Per.(SAS-I) -1/85 dated 30-01-2008 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT
 Secretariat Administration Services-I

NOTIFICATION

Shimla-171002, 1st February, 2008

No. Per.(SAS-I) A(3)-1/85-I.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following

Rules further to amend the Recruitment and Promotion Rules for the post of **Mali** Class-IV (Non Gazetted) in the Department of Personnel (Secretariat Administration) Himachal Pradesh notified *vide* notification No.Per(SA-1)(A-3)3/83 dated 18-9-1996, namely :—

1. Short Title and Commencement.— (1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Department of Personnel (Secretariat Administration) **Mali**, (Class-IV Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2008.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure “A”.—In Annexure “A” to Himachal Pradesh Department of Personnel (Secretariat Administration) **Mali**, (Class-IV Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996.—

(a) In Col. No. 6 for the words and figures“ Between 18 years to 38 years” the words and figures “Between 18 years to 45 years” shall be substituted;

(b) For the existing title of column No. 10 the following shall be substituted, namely :—

“Method of recruitment- whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various method.”

(c) For the existing provision against column No, 10, the following shall be substituted, namely :—

“ 100 % BY direct recruitment or on contract basis”

(d) For the existing entries against column 14 the following shall be substituted, namely :-

"A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India." and

(e) After the existing column No. 15 the following shall be inserted, namely :—

15 (A) Selection for the appointment to the post by contract appointment.—(i) **CONCET:**
(a) Under this policy **Mali**, in the Secretariat Administration will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis;

(b) The candidates will be selected by advertising the vacant posts in two leading news papers;

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in the Recruitment and Promotion Rules;

(d) Contractual **Mali**, so selected under these Rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in Govt. job at any stage.

(e) The age and qualification for the contract appointment will be as per the the provisions contained in Col. 6 & 7 of the Recruitment & Promotion Rules;

(ii) Contractual Emoluments :— The **Mali**, appointed on contract basis will be paid consolidated contractual amount of Rs. 3930/- (i.e. initial of the basic pay scale + dearness pay) per

month. An amount of Rs.100/- per annual increase, in contractual emolument for second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(iii) **Appointing / Disciplinary Authority:**—As per the Standing Orders issued by the Government from time to time.

(a) The Secretariat Administration Department well in advance will seek the approval to fill up the vacancies by giving full justification from the Competent Authority;

(b) After obtaining the approval to fill up the vacant post(s) on contract basis the Department will advertise the details of the vacant posts in two leading Newspapers and invite the applications of the eligible candidates having qualifications and other eligibility conditions as prescribed in these Rules;

(c) Selection for appointment to the post in the case of Contract appointment / recruitment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard /syllabus etc. of which will be determined by the Selection Committee.

(v) **Committee for Selection :**—As may be constituted by the Competent Authority from time to time.

(vi) **Agreement :**—After the selection of a candidate concerned, he / she Shall be required to execute an agreement with the Government as per Annexure-“B” of these Rules.

(vii) **Terms and Conditions:**—(a) The **Mali**, appointed on contract basis will be paid fixed contractual amount @ Rs.3930/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). The Contract Appointee will be entitled to an increase in the contractual amount @ Rs. 100/- (equal to annual increase in the pay scale) per annum for second and third consecutive years and no other allied benefits such as grant of any higher grade(s) except the above consolidated amount shall be given;

(b) The Contractual Appointment shall be purely on temporary basis. Such an appointment is liable to termination in case the above performance and conduct of the contract appointee is not found satisfactory by the Appointing Authority;

(c) Contractual appointment shall not confer any right to the contractual appointee for regularization of his or her service.

(d) Contract Appointee shall be entitled for one day's casual leave after rendering one month's continuous service. This leave shall accumulate for one calendar year and thereafter it will lapse. No other kind of leave shall be admissible to the contractual appointee. Only maternity leave shall be admissible to a female contractual appointee as per the concerned leave Rules;

(e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Competent Authority shall amount to action as to the termination of the contract. No remuneration for the unauthorised absence shall be payable in such lapse(s);

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on official tour in connection with discharging of his/her official duties at the same rate as applicable to a counterpart regular employee on the minimum of the pay scale.

(h) Contract appointee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc.

(i) Transfer of Contract Appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(viii) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT:—The candidate engaged on contract basis under these Rules shall have no right to claim regularization/permanent absorption as **Mali** in the Department at any stage.

By order
Sd/-
Secretary.

Form of contract/ agreement to be executed between the **Mali**, and the Government of Himachal Pradesh through Secretary (SA).

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____. Between _____ Sh./Smt. _____ S/o/D/o Shri _____ R/o _____ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), The Governor of Himachal Pradesh through Special Secretary Secretariat Administration Himachal Pradesh (here-in after the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Mali**, on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Mali**, for a period of 1 year commencing on _____ day of _____ and ending on _____ the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____. And information notice shall not be necessary.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 3930/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.
5. Contractual **Mali**, will be entitled for one day's casual leave after putting in one month's service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual **Mali**. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Mali**, will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
7. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.
8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
9. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.
10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESECNCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____

(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____

(Name and Full Address)

ब अदालत श्री देव राज शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी ढटवाल, उप-तहसील बिझड़ी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री अमर जीत, वासी गांव, धगोटा, तप्पा व उप-तहसील ढटवाल (बिझड़ी),
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।

विषय.—जन्म तिथि पंजीकरण करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री अमर जीत, वासी गांव, धगोटा, तप्पा ढटवाल, जिला हमीरपुर ने इस न्यायालय में अपने पुत्र श्री धीरज कुमार की जन्म तिथि 1-12-1999 को ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है। इसके पक्ष में उन्होंने शपथ-पत्र अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) हमीरपुर का प्रमाण-पत्र, अप्राप्या प्रमाण-पत्र, साथ संलग्न किये हैं।

अतः इस इशतहार अदालती द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी इस जन्म तिथि के पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 20-10-2008 से पूर्व आकर अपनी आपत्ति पेश कर सकता है बाद में आने पर कोई आपत्ति काबिले गौर न होगी। तथा नियमानुसार आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 9-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देव राज शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी ढटवाल,
उप-तहसील बिझड़ी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री देव राज शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी ढटवाल, उप-तहसील बिझड़ी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री दीना नाथ, वासी गांव, महारल, तप्पा व उप-तहसील ढटवाल (बिझड़ी),
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी

विषय.—मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री दीना नाथ, वासी गांव, महारल ने इस न्यायालय में अपने ससुर स्व0 श्री अनन्त राम जो कि दिनांक 4-12-2007 को स्वर्ग सिधारे थे का मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र पेश किया है। इसके पक्ष में उन्होंने अपना शपथ-पत्र पेश किया है।

इस इशतहार अदालती द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस मृत्यु की तिथि बारे कोई एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 20-10-2008 से पूर्व आकर अपना एतराज पेश करे, न आने पर माना जाएगा कि कोई आपत्ति न है तथा आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 9-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देव राज शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी ढटवाल,
उप-तहसील बिझडी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजापनुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा
दरुस्ती

तारीख सुनवाई
7-11-2008

1. श्री काली कुमार, 2. श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री वचित्र सिंह, 3. सीमा देवी पुत्री श्री वचित्र सिंह, 4. जानकी देवी बेवा श्री वचित्र सिंह, 5. श्री प्रकाश चन्द, 6. श्री रूप लाल, 7. श्री रमेश चन्द पुत्रगण श्री फित्या, 8. चचलो देवी पुत्री श्री फित्या, 9. वातो देवी बेवा श्री फित्या, वासीगण टीका बजाहर, तपा जंगल राजगिर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) . . प्रार्थीगण।

बनाम

1. पार्वती देवी बेवा श्री महीफत, 2. रामेश्वरी देवी पुत्री श्री महीफत, 3. सवित्री देवी, 4. वीना देवी, 5. निर्मला देवी पुत्रीगण श्री महीफत, 6. श्री सुदेश कुमार पुत्र श्री महीफत, 7. भगत राम के वारयान श्री कुलदीप, श्री बलजीत, जानकी देवी, 8. श्री देश राज, 9. श्री रमेश चन्द, 10. श्री कृष्ण चन्द पिसरान श्री भलखू, 11. श्री राज सिंह, 12. श्री सुनील कुमार पिसरान भुक्कड़, 13. श्री सुभाष चन्द, 14. श्री रणजीत सिंह पिसरान श्री सुर्जन, 15. शाली ग्राम, 16. श्री जगत राम पुत्रगण श्री श्यामा, 17. बिमला देवी बेवा श्री रोशन लाल, 18. बीना देवी, 19. सन्नो देवी, 20. लता कुमारी पुत्रीगण श्री रोशन लाल, 21. श्री राज कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, वासीगण टीका बजाहर, तप्पा जंगल राजगिर, तहसील सुजानपुर . . फरीकदोयम।

प्रार्थना-पत्र बराये दरुस्ती अराजी खाता नम्बर 61, खतौनी नम्बर 99, ता0 111, खसरा नम्बरान कित्ता, 7 रकवा 47-1 K.M., जमई व खसरा नम्बर 475, मिन रकवा 2-7 K.M. व खसरा नम्बर 475 मिन जानिव 2-14 K.M., कुल रकवा 5-1 K.M. व खसरा नम्बर 472, मिन जानिव 0-10 K.M. व खसरा नम्बर 475, मिन रकवा 1-2 K.M. खसरा नम्बर 491 मिन रकवा 0-9 कुल रकवा 2-1 K.M. व खसरा नम्बर 469, रकवा 0-18 K.M. व रकवा नम्बर 472 मिन, रकवा 0-8 K.M. व खसरा नम्बर 475 मिन, रकवा 0-7 K.M. व खसरा नम्बर 491 मिन, रकवा 0-15 K.M., कित्ता 4 कुल रकवा 2-8 K.M. व खसरा नम्बर 29 रकवा 6-16 K.M., मीजान खसरा कित्ता 18 रकवा 63-7 K.M. व खसरा नम्बर 470 मिन, रकवा 4-10 K.M. व खसरा नम्बर 470 मिन रकवा 3-4 K.M. व खसरा नम्बर 470 रकवा 0-18 K.M. व खसरा नम्बर 474 मिन रकवा, 2-17 K.M. व खसरा नम्बर 474 मिन, रकवा 1-4 K.M. व खसरा नम्बर 474, मिन रकवा 0-9 अनुसार जमावन्दी साल 2002-03 काक्या टीका बजाहर, तपा जंगल राजगिर, तहसील सुजानपुर।

श्री काली कुमार आदि प्रार्थीगण ने उपरोक्त भूमि की दरुस्ती के लिए इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दे रखा है। इस अदालत द्वारा रामेश्वरी, सवित्री देवी, वीना देवी, निर्मला देवी, लता कुमारी फरीकदोयम को कई बार सम्मन जारी किये गये। मगर इन पर सम्मन की तामील हस्व जावता न हो रही है। मुताविक रिपोर्ट तामिल कुन्निदा यह कही दूसरी जगह रिहायश करते हैं। प्रार्थी का कहना है कि उसे उनका पता नहीं मिल रहा है। इसलिए उसने गुजारिश की है कि इन्हें बजरिया इश्तहार राजपत्र तलव किया जाये। इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त फरीकदोयम पर साधारण तरीके से सम्मन की तामिल नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त फरीकदोयम को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उन्हें उपरोक्त अराजी की दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-11-2008 को सुबह 10.00 बजे अदालत में असालतन या

वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा गैर-हाजिर की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 2-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजापनुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर :

तारीख सुनवाई
20-10-2008

श्री रतो राम पुत्र श्री देवी दास, वासी दाडला, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती।

श्री रतो राम बनाम आम जनता

श्री रतो राम पुत्र श्री देवी दास ने इस अदालत में दिनांक 5-8-2008 को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका पंचायत रिकार्ड में व अन्य प्रमाण-पत्रों में श्री रतन चन्द दर्ज है तथा कागजात माल में श्री रतो राम दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि यह दोनों नाम उसी के ही हैं। प्रार्थी अब दुरुस्ती करवा कर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम श्री रतो राम उर्फ रतन चन्द करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-10-2008 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 21-8-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर
(हि0 प्र0)

श्रीमती इन्दु पत्नी श्री संजीव कुमार, टीका पलभू, डाकघर कक्कड़, तहसील सुजानपुर, जिला
हमीरपुर (हि0 प्र0) . . प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी ।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती इन्दु पत्नी श्री संजीव कुमार, वासी पलभू ने दिनांक 9-7-2008 को इस न्यायालय में एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसके लड़के का जन्म 7-7-2003 ग्राम पलभू, डाकघर कक्कड़, तहसील सुजानपुर में हुआ है। मगर अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत वजरोल के अभिलेख में दर्ज न करवाया है इसलिए अब करवाना चाहते हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि जिसे उपरोक्त निखिल कुमार के जन्म पंजीकरण को ग्राम पंचायत वजरोल के रिकार्ड में दर्ज कराने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-10-2008 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर—हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 30-8-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सुजानपुर,
तहसील सुजानपुर टीहरा, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सुजानपुर, तहसील सुजानपुर,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्रीमती जीवना देवी पत्नी श्री मेहर सिंह, वासी जंगल, मौजा जंगल राजगिर, तहसील
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) . . प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी ।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती जीवना देवी पत्नी श्री मेहर सिंह, वासी जंगल, मौजा जंगल राजगिर, तहसील सुजानपुर ने दिनांक 4-4-2008 को इस न्यायालय में एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसकी लड़की आंकाक्षा देवी का जन्म 17-4-2003 को ग्राम जंगल, डाकघर जंगल, तहसील सुजानपुर में हुआ है। मगर अज्ञानतावश प्रार्थीया इसके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत जंगल के अभिलेख में दर्ज न करवा सकी है तथा अनुरोध किया है कि इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत जंगल के रिकार्ड में दर्ज किया जाये।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आंकाक्षा के जन्म पंजीकरण को ग्राम पंचायत जंगल के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2008 को सुबह 10.00 बजे असातन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 3-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सुजानपुर,
तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

योजना विभाग
(अर्थ एवं संख्या)

अधिसूचना

तारीख: 12 सितम्बर, 2008

संख्या: पी0एल0जी0-ए(3)-3/2007(अधीक्षक, ग्रेड-II).— हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में अधीक्षक ग्रेड-II, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना के साथ संलग्न "उपाबंध-क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में अधीक्षक ग्रेड-II, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,
अरविन्द मैहता
प्रधान सचिव।

उपाबंध - 'क'

हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में अधीक्षक ग्रेड -II, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम : अधीक्षक ग्रेड-II ।
2. पदों की संख्या : 02 (दो) ।
3. वर्गीकरण : वर्ग-II (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं।

4. वेतनमान : (विस्तृत रूप में अंकित दरें) 6400—200—7000—220—8100—275—10300—340—10640 रुपए।

5. चयन पद अथवा अचयन पद : अचयन ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु : लागू नहीं ।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं: लागू नहीं ।

8. क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं : लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।

10. भर्ती की पद्धति :— भर्ती सीधी होगी, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता : शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा : वरिष्ठ सहायको में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका छह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवा काल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण :—अन्तिम परन्तुक के अर्न्तगत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोब्लिआईज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अर्न्तगत भर्ती किया गया है और इनके अर्न्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अर्न्तगत भर्ती किया गया हो और इनके अर्न्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिये गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा: जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षा : लागू नहीं ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन : लागू नहीं ।

16. आरक्षण : सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा : लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति : जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

[Authoritative English text of Government Notification No. PLG-A(3)-3/2007 (Supdt. Gr.-II)
Dated 12-9-2008, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PLANNING DEPARTMENT (Economics & Statistics)

NOTIFICATION

12th September, 2008

No. PLG-A(3)-3/2007(Supdt. Gr.-II).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion

Rules to the post of Superintendent Grade-II, Class-II, (Non-Gazetted) in the Department of Economics and Statistics, Himachal Pradesh as per “Annexure-A” attached to this notification.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Economics and Statistics, Himachal Pradesh, Superintendent Grade-II, Class-II, (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion rules, 2008.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,
Arvind Mehta,
Principal Secretary.

“ANNEXURE-I”

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SUPERINTENDENT GRADE-II, CLASS-II, (NON GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF ECONOMICS AND STATISTICS , HIMACHAL PRADESH.

1. *Name of the post.*—Superintendent, Grade-II
2. *Number of post(s).*—02 (Two)
3. *Classification.*—Class-II (Non Gazetted) Ministerial Services.
4. *Scale of pay.*—Rs.6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640.
(Rs. given in expanded notation).
5. *Whether “Selection” post or “Non-Selection” post.*—Non Selection.
6. *Age for direct recruitment.*—Not applicable.
7. *Minimum educational & other qualifications required for direct recruitment.*—Not applicable.
8. *Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s).*—Not applicable.
9. *Period of probation, if any.*—Two years’ subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. *Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.*—100% by promotion.
11. *In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.*—By promotion from amongst the Senior Assistants with six years regular service or regular combined with continuous ad-hoc service in the grade.

(1) In all cases of promotion, the continuous ad-hoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken in to account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the ad-hoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that:—

In all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on ad-hoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, ad-hoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the ad-hoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, ad-hoc services rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. *If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.*—As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. *Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.*—As required under the law.

14. *Essential requirement for a direct recruitment.*—Not applicable.

15. *Selection for appointment to post by direct recruitment.*—Not applicable.

16. *Reservation.*—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. *Departmental Examination.*—Not applicable.

18. *Powers to Relax.*—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).